(घ) भुगतान में विलंब करने या अब तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के०पी० सिंह देव) : (क) से (ग) 30-6-94 की स्थिति के अनुसार, 48,616 लंबित विज्ञापन बिलों के संबंध में 9,93,89,865.52 रु० की राशि देय थी । वर्षवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

वर्ष	बिल सं०	दावा की गई राशि
1991-92	5744	1,13,79,637.77
1992-93	5998	1,42,76,257.17
1993-94	29,529	6,07,57,369.27
1994-95	7345	1,29,76,601.31
(जून, 1994 तक जोड़	48616	9,93,89,865.52

(घ) मुख्यत: हस्तचालित प्रक्रिया के स्थान पर कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया अपनाये जाने के परिणामस्वरूप वर्ष 1991 से बिलों के भुगतान में विलब हुआ । शुरू में, कम्प्यूटर में कुछ प्रारंभिक कठिनाइयां उत्पन्न होने और बाद में प्रणाली में एक बड़ी खराबी आ जाने के कारण अत्यधिक मात्रा में बिल जमा हो गये थे ।

Langhagewise number of news papers

2002. SHRI MOHAMMED AFZAL *alias* MEEM AFZAL: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) the languagewise number of newspapers published in 1993; and

(b) what is the circulation of newspapers languagewise, during the said period?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) and (b) The details of newspapers, including their number language, circulation, etc. published in the country are compiled by RNI on the basis of the annual statements required to be submitted to him by the publishers under the PRB Act. These are published every year in the form of a report entitled "Press in India", which is required to be submitted to the Government by 30th September every year. The RNI is still in the process of compiling the information sought in the question for the year 1993.

भारतीय फिल्म उद्योग में संकट

2003. **श्री दिग्विजय सिंह :**
श्री सत्य प्रकाश मालवीय :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास भारतीय फिल्म उद्योग को संकट से उबारने और उसकी आगे प्रगति के लिये कोई कार्यक्रम है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या राज्यों के सूचना मंत्रियों ने सरकार से वीडियो पार्लरों और केबल आपरेटरों पर मनोरंजन कर लगाने की सिफारिश की है ; और

(ग) यदि हां, तो उन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और